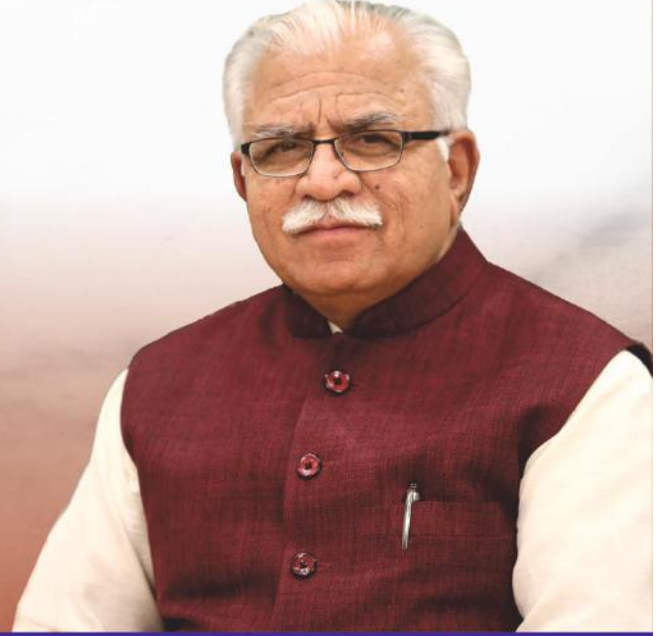




हरियाणा सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री



श्री मनोहर लाल  
मुख्यमंत्री

“इतिहास गवाह है कि प्रदेशवासियों ने हर विपत्ति का सामना बुलंद हौसलों से किया है, जिसकी बदौलत हरियाणा का प्रगति रथ न कभी रुका है और न कभी रुकेगा। सरकार ने इस संकट के दौर में सभी वर्गों को हरसम्भव मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। मैं, तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणावासी इस संकट की घड़ी में अपना सम्पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। यही साथ और समर्थन हमें इस संकट से निकलने में मदद करेगा। मैं, उम्मीद करता हूं कि हम 'आत्मनिर्भर हरियाणा' की ओर मिलकर एक मजबूत कदम बढ़ायेंगे।”

- मनोहर लाल  
मुख्यमंत्री, हरियाणा

**बुलंद हौसले, बुलंद फौसले**



## किसान कल्याण

- जल संरक्षण के लिए धान बाहुल्य क्षेत्रों में 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत **₹ 7000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता**।
- 'नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना-2019' के तहत 1,11,817 किसानों की **₹ 23.80 करोड़ की जुर्माना राशि माफ**।
- फसली ऋणों से राहत की 'एकमुश्त निपटान योजना' में 4.10 लाख किसानों की **₹ 1314.31 करोड़ की ब्याज व जुर्माना राशि माफ**।
- 'भावान्तर भरपाई योजना' में 19 फसलें और सब्जियां शामिल।
- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 'पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना' लागू।
- पांच जिलों में 'अटल किसान-मजदूर कैंटीन' योजना शुरू, मिलेगा **₹ 10 में भोजन**।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

महामारी के बावजूद हर किसान के हरेक दाने की सरकारी खरीद

फसली ऋणों पर ब्याज दर में 4 प्रतिशत की छूट

मंडियों में किसानों व आढ़तियों को **₹ 10 लाख का बीमा कवर**

## शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

- HTET की मान्यता **5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष** की और साथ ही परीक्षा केन्द्र भी परीक्षार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए।
- कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें**।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

'एजुसैट', 'शिक्षा सेतु एप', 'संपर्क बैठक एप' इत्यादि के माध्यम से छात्रों को शिक्षा जारी

विद्यार्थियों के शिक्षा ऋण के **तीन महीने के ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा वहन** करने का निर्णय, लगभग 36 हजार विद्यार्थियों को **₹ 40 करोड़ का लाभ**

## स्वस्थ हरियाणा-स्वस्थ भारत

- 'आयुष्मान भारत योजना' में 1,11,226 मरीजों का **₹ 146.29 करोड़ का निःशुल्क इलाज**।
- प्रदेश में मरीजों के लिए **400 मोबाइल डिस्पेंसरी** शुरू।
- प्रदेश में **लिंगानुपात** की दर अप्रैल, 2020 में सुधरकर **913** हुई।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

**447 नये चिकित्सकों की भर्ती**

कोविड वार्ड में सीधे तौर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन दोगुना

सभी जिलों में टैली मेडिसिन की सुविधा के लिए 1024 सेवारत डॉक्टरों द्वारा 23,170 फोन कॉल्स पर मरीजों को मुफ्त सलाह व दवाइयां

प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का **मुफ्त इलाज**

कोविड-19 टेस्ट के लिए **प्रदेश में 14 टेस्टिंग लैब**



## कर्मचारी कल्याण

- सरकारी कर्मचारी का 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित के लिए 'नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम'।
- 500 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले 10 विभागों में ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति का प्रारूप तैयार।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

कोविड-19 के लिए काम कर रहे सभी सरकारी व निजी डॉक्टरों को ₹ 50 लाख, नर्सों व सुरक्षाकर्मियों को ₹ 30 लाख, पैरा-मैडिकल स्टाफ को ₹ 20 लाख, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी व आशा वर्करों और सफाई कर्मचारियों को ₹ 10 लाख का जीवन बीमा कवर

## व्यापार जगत को राहतें

- 'हरियाणा एम.एस.एम.ई. रिवाइवल ब्याज लाभ योजना' के तहत वेतन के भुगतान और अन्य खर्च हेतु लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर अधिकतम 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से 100 प्रतिशत ब्याज का लाभ, जिसकी अधिकतम राशि ₹ 20 हजार प्रति कर्मी है।
- एम.एस.एम.ई. के लिए नये विभाग का सृजन
- मुद्रा लोन की 'शिशु योजना' के तहत ₹ 50 हजार तक ऋण के ब्याज में से 2 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मई, 2020 में ओपन हाऊस आयोजित। 60 कम्पनियों ने निवेश की सहमति जताई।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

मार्च व अप्रैल माह के लिए ₹ 40,000 तक प्रतिमाह के बिजली के फिक्स चार्ज वाले उद्योगों को ₹ 10,000 की सीलिंग के साथ फिक्स चार्ज में छूट तथा ₹ 40,000 से अधिक फिक्स चार्ज वाले उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत की छूट

अप्रैल से अब तक  
₹ 162 करोड़ का वैट रिफण्ड

लॉकडाउन में 53,805 उद्यमों में व  
36,24,295 कामगारों को काम करने की अनुमति

## ग्रामीण व शहरी विकास

- 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2019' में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर।
- सिरसी (करनाल) से गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने वाले 'डिजिटल मैप' का शुभारम्भ, इसके तहत गांवों में रहने वाले हर मकान मालिक को मालिकाना हक दिया गया।
- 'जल-जीवन मिशन' के तहत ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए नीति बनाई।
- 'हाऊसिंग फॉर ऑल' नामक (सभी के लिए आवास) नये विभाग का सृजन।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

2,588 पंचायतों को सेनिटाइजेशन के लिए ₹ 5.18 करोड़ की राशि जारी

कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु सभी नगर पालिकाओं को ₹ 288.92 करोड़ का अनुदान





## आधारभूत संरचना का सुदृढ़ विकास

- ₹ 178.88 करोड़ की लागत से 4 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण।
- ₹ 58.10 करोड़ की लागत से 3 आर.ओ.बी. व आर.यू.बी. बनाए गये।
- होडल (पलवल) में ₹ 22 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महाविद्यालय बनाया।
- पलवल बस अड्डे व वर्कशाप का ₹ 11 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण।
- अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के नागरिक अस्पतालों को 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों का बनाया गया।
- मूनक (करनाल) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नारायणा (करनाल) व कोयल (जींद) में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले।
- 301 किलोमीटर लम्बी नई बिजली लाइनें बिछाई तथा 19 नए सब-स्टेशन स्थापित व 35 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि।

### विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर

- प्रदेश में ₹ 1365.74 करोड़ की लागत से 52 आर.ओ.बी. व आर.यू.बी.।
- ₹ 874.49 करोड़ की लागत से 7 सड़कों का।
- रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन ₹ 697.85 करोड़ की लागत से।
- कोरियावास (महेन्द्रगढ़) में ₹ 598 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज।
- जींद में ₹ 664 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज।
- ₹ 194.30 करोड़ की लागत से कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकूला में एक-एक व फरीदाबाद में 2 नर्सिंग कॉलेज।



## गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद

- 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' में 6,23,108 परिवारों को ₹ 4,000 प्रति परिवार की दर से ₹ 211.62 करोड़ की सहायता।
- सभी सामाजिक पेंशन ₹ 2000 से बढ़ाकर ₹ 2250, दिव्यांग बच्चों की वित्तीय सहायता ₹ 1400 से बढ़ाकर ₹ 1650 व निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता ₹ 1100 से बढ़ाकर ₹ 1350 मासिक की।
- सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कैंसर पीड़ित व किडनी के रोगी को ₹ 2250 मासिक पेंशन देने का निर्णय।
- राज्य परिवहन की बसों में कैंसर पीड़ित के एक सहयोगी को भी मुफ्त यात्रा सुविधा।
- गरीब व जरूरतमंद 15,10,333 परिवारों को ₹ 636.16 करोड़ की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में दी।
- 3 लाख गरीबों को अपना काम शुरू करने हेतु 2 प्रतिशत ब्याज पर ₹ 15 हजार तक ऋण।



### कोरोना महामारी के दौरान फैसले

<b>₹ 1200 करोड़ का वित्तीय पैकेज जारी</b>	
प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए 'हरियाणा कोरोना रिलीफ फण्ड' बनाया,	
27,01,077 राशन कार्डधारक परिवारों को ₹ 154 करोड़ का 3 महीने का मुफ्त राशन	Distress Ration Token (DRT) द्वारा राशन कार्ड रहित 4,86,400 परिवारों को 2 महीने का मुफ्त राशन
सभी जिलों में 600 राहत केन्द्रों में 90,000 से अधिक लोगों के मुफ्त उठरने, खाने व चिकित्सा की व्यवस्था	96 ट्रेनों व 5200 बसों के माध्यम से 3,28,000 श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया
'मिड डे मील' के तहत 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों व आंगनवाड़ी केन्द्रों के 10 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं के घर-द्वार पर राशन पहुंचाया	